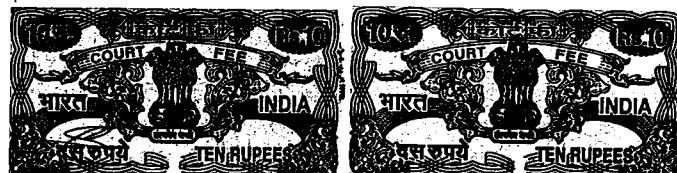


न्यायालय : मानवीय राजस्व मॉडल मध्यप्रदेश खालियर.

राज. निग. प्रक्र. ०१

/०१४



R - २६९ - ३१५

वैश्वपति तिवारी तनय स्व० रामनिवास तिवारी निवासी मोहल्ला पड़ा,  
तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य०

----- आवेदक -----

विरुद्ध  
द्वा

कामना सिंह पत्नी स्व० सतोष सिंह निवासी ग्राम सलैया, पो०  
मणिगंवा०, तहसील सिरमोर जिला रीवा, मध्य०

----- अनावेदक -----

ब्रह्म आज दिन २७-६-६६ को  
प्रस्तुत

कलाकार औफ कॉर्ट  
राजस्व मॉडल म.प्र. वर्षालेवर

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील  
हुजूर, जिला रीवा, दिनांक १४.०७.०१४ जो  
प्रकरण क्र. १४१-४-७०/०१२-१३ में पारित  
किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य० भू० रा० त०  
१९५९ इ० ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :

१०१। यह कि प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के  
विपरीत होने से निरस्त किसाने योग्य है ।

१०२। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के सम्म आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर  
प्रारंभिक आपत्ति की थी, कि प्रकरण धारा २५० के अधीन प्रचलन योग्य

४८ अनुदा ०१

निरंतर ०२पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2969—तीन / 14

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-8-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री जे० एस०गौड उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये।</p> <p>आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत धारा 250 के आवेदन पत्र पर सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति की गयी थी कि प्रकरण धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य नहीं है जिसे तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक—14.07.14 से मात्र यह लिख कर निराकृत कर दिया कि आवेदन सीमांकन उपरांत प्रस्तुत किया गया है, ऐसी दशा में संहिता की धारा 250 का आवेदन प्रचलन योग्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में जो नक्शा है उसमें सुधार या तरमीम नहीं हुई है ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण नक्शों के आधार पर किया गया सीमांकन भी अनुचित है। इसके अलावा वही तथ्य दुहराये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है।</p> <p>अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया कि आवेदिका श्रीमती कामना सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक—20.04.13 को सीमांकन कार्यवाही राजस्व निरीक्षण द्वारा की गयी जिसमें आवेदिका के सर्वे क्रमांक—534/1 के कुछ रकवे पर आवेदक बंशपति पिता रामनिवास का अनाधिकृत कब्जा पाया गया, जिसे कब्जा मुक्त</p>	

कराये जाने हेतु संहिता की धारा 250 की तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है। अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्कों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 में अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है तथा कार्यवाही प्रचलित होकर विचाराधीन है। राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20.4.13 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि अनावेदिका के सर्वे कमांक-534/1 के अंश भाग 1.9 जरीब लम्बाई एवं 0.40 जरीब चौड़ाई पर आवेदक वंशपति तिवारी का कब्जा होना अंकित है इस सीमांकन रिपोर्ट का राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक-22.4.13 को अंतिम रूप दिया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक-निग.-2885/तीन/13 पर दायर होकर आदेश दिनांक-15.10.13 को इस निर्देश के साथ प्रचलन योग्य न होने से अग्राहय की गयी कि यदि आवेदक चाहे तो अपने भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक-06.01.2014 को आवेदक वंशपति के सर्वे कमांक-535 रकवा 0.105 है व 536 रकवा 0.028 है के सीमांकन की कार्यवाही की गयी जिसके अनुसार यह स्थिति प्रकट हो रही है कि खसरे में आवेदक के दोनों सर्वे नम्बरों का कुल रकवा 0.133 है दर्ज है जबकि मौके पर बने नक्शे के अनुसार रकवा 0.101 है। पंचनामा दिनांक-6.1.2014 में यह स्पष्ट अंकित है कि मौके पर आवेदक वंशपति का कब्जा पटवारी नक्शे के मान से लम्बाई-चौड़ाई से अधिक पर पाया गया है।

प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार द्वारा की जा रही बेदखली की कार्यवाही से संबंधित है। सीमांकन कार्यवाही से संबंधित विवाद इस समय इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

प्रकरण में विद्यमान विषय वस्तु के संबंध में न्यायसिद्धांतों का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अमरी बाई विरुद्ध मांगीलाल, 2005 राजस्व निर्णय 178(राजस्व मण्डल) में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि जहां धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन का प्रकरण पूर्व में विनिश्चित किया जा चुका हो तो धारा 250 के अधीन कार्यवाही में इसमें आक्षेपित करना उचित नहीं होगा।

प्रकरण में उभयपक्ष अभिषक्तों के तर्कों को सुना गया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन तथा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तहसीलदार हुजूर द्वारा अपने प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक-14.7.14 में पारित आदेश चूंकि अंतिम आदेश नहीं है एवं अभी उसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन होकर प्रचलित है, अतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के समय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेखित अनुसार इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था कि आवेदक के सर्वे क्रमांक-535 व 536 के खसरे में अंकित रकवे से पटवारी नक्शा में उक्त सर्वे नम्बरों की आकृति कम रकवे की होने से विवाद की स्थिति बनी है। दूसरी ओर अनावेदिका कामना सिंह की भूमि के सीमांकन दिनांक-20.4.13 के अनुसार कामना सिंह के रकवे के अंशभाग पर आवेदक का कब्जा होना भी रिकार्ड पर विद्यमान है। प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही के प्रचलित होने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं पाया गया है।

9

R- 2969/II/14

रीका

ऐसी स्थिति में प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत कार्यवाही करें ताकि आवेदक एवं अनावेदिका को खसरा अभिलेख के अनुसार उनके द्वारा धारित रकवा मौके पर पूरा-पूरा मिल सके। इसके प्रकाश में ही मौके पर से आवेदक का कब्जा हटाने/ नहीं हटाने के संबंध में विधि सम्मत निर्णय लेकर कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। तहसीलदार पालन प्रतिवेदन भेजें।

(आशीष श्रीवास्तव)  
सदस्य